बिहार विधान सभा बादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एक विधान सभा का कार्य विवरण सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १२ अप्रैल, १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

Short Notice Questions and Answers.

सासामुसा चीनी मिल का बंद होना ।

२६८ । श्री शिवकुमार पाठक—क्या मंत्री, विकास (ईख) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सासामुसा चीनी मिल ता० १९ मार्च, १९५५ को ८ बजे सुबह बंद कर दिया गया और गेट के बाहर जो गाड़ियां थीं, वापस लौटा दी गईं ;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो ऐसा क्यों हुआ और जो गाड़ियां लौटा दी गईं उनके लिये क्या इंतजाम किया गया तथा उनको जो दिक्कतें उठानी पड़ीं और उनके ऊख में जो सुखवन गया उसका जिम्मेवार कौन है ;

(ग) क्या यह बात सही है कि उस मिल के रिजर्व एरिया में जैसे मनियारा फार्म, रामपुर मावों, दियारा विजयपुर, बेलवा और हेमबरादाहा आदि गांवों में भी बहुत ऊख बाकी छोड़कर मिल बंद कर दिया गया है ;

(घ) क्या यह बात सही है कि किसी मिल को अपने रिजर्व एरिया में कुछ भी ऊख छोड़कर मिल बंद करने का अधिकार नहीं है ;

(ङ) यदि खंड (ग) और (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो ऐसा क्यों हुआ और उस एरिया के बाकी ऊखों के लिये क्या इंतजाम किया गया तथा संबंधित किसानों को हरासमेंट और ऊख के सुखवन के लिये मुआवजा दिलाने का विचार क्या सरकार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—(क) सासामुसा चीनी मिल ता० १९ मार्च, १९५५ को ८ बजे सुबह में बंद कर दिया गया और उस समय तक गेट के बाहर कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ी गयी थी । फलतः किसी गाड़ी के वापस होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) ऊपर के उत्तर दे देने के बाद यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उत्तर ना है ।

(घ) उत्तर हां है ।

मेहशी में बटन उद्योग।

४१९। श्री ब्रज बिहारी शर्मा—क्या मंत्री, विकास (उद्योग विभाग), यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि भारतीय संघ के अंदर सीप बटन उद्योग का एक मात्र कारखाना चम्पारण जिला के मधुवन थाना के मेहशी ग्राम में है ;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो १९५३ से १९५५ तक कितने रुपयों का बटन बनता रहा है ;

(ग) इस उद्योग की अवस्था इस समय कैसी है ;

(घ) इस उद्योग को उन्नत बनाने के हेतु स्टेट सरकार ने कौन-कौन से प्रयत्न किये हैं ;

(१) क्या सरकार सहकारिता के केन्द्रों द्वारा बटन बेचवाने का प्रबंध करवा सकती है ;

(२) क्या सरकार प्लासटिक के बने बटनों को रोक कर सीप-बटन की रक्षा करना चाहती है ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—(क) यह बात सही है कि चम्पारण जिले के मधुवन थाने के मेहशी ग्राम में सीप-बटन उद्योग के कई एक कारखाने स्थित हैं। देश में दूसरे स्थान में ऐसे कारखाने हैं कि नहीं निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(ख) इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) इस उद्योग की जो हालत पहले थे वैसी नहीं है और दूसरे प्रकार के बटनों की मांग की वजह से इसकी मांग कुछ कम हो गयी है।

(घ) इस उद्योग की उन्नति के लिये सरकार स्टेट एड टू इंडस्ट्रीज ऐक्ट में उनलोगों को कर्ज देती है जो क़र्ज चाहते हैं। सरकार ने इसकी रक्षा के लिये टेरीफ बोर्ड के सामने मांग की थी लेकिन इसकी रक्षा के लिये टेरीफ बोर्ड ने कोई सिफारिश नहीं की।

(१) यों तो उत्पादकों पर निर्भर है कि अपना माल बेचने के लिये सहकारी समितियां बनावें। हां, यदि वे सहकारिता समितियां या कोई दूसरी समितियां बनावें तो सरकार उसके बनाने में या दूसरे प्रकार से उन्हें सहायता दे। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये एक ऐसी स्कीम बनायी जा रही है।

(२) प्लास्टिक के बने बटनों से सीप के बने बटनों की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार ने सीप की बटन की रक्षा के लिये टेरीफ बोर्ड के सामने सिफारिश की थी लेकिन टेरीफ बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से रक्षा के लिये सिफारिश नहीं की।

PAYMENT BY PACHRUKHI SUGAR FACTORY.

846. Shri DAROGA PRASAD ROY : Will the Minister in charge of the Development (Cane) Department be pleased to state—

(*a*) (*i*) whether it is a fact that the Pachrukhi factory is not paying the prices of cane to the canegrowers in the Sitalpur area (Saran) ?

(*ii*) whether it is a fact that no price has been paid to the Kisans of Sonepur station as yet and about Rs. 20,000 are still lying unpaid with the factory ;

(*b*) whether it is a fact that the factory has deliberately stopped the payments to the Kisans in villages Bajahian, Chainpur and Khirikia in Parsa P.-S. ;

(*c*) whether it is a fact that the Kisans being harassed and depressed by the attitude of this factory has left the cane cultivation this year to a great extent ;

(*d*) what steps Government have taken to protect the Kisans from the non-payment of the factory ;

(*e*) whether Government see the desirability of not allotting this area to Pachrukhi factory any more in view of the hardship and harassment caused to the Kisans by this factory ?

Shri MAHESH PRASAD SINHA : (*a*) (*i*) It is not a fact that Pachrukhi factory is not paying the price of cane to the canegrowers in Sitalpur area but a part of the price has not been paid.

(*ii*) Separate figures for the amount to be payable for the purchase of cane at Sonepur is not available but as already stated above up to 10th April, 1955, a sum of Rs. 67,660-5-9 for cane purchased at all the stations, namely, Sitalpur, Nayagaon and Sonepur is still to be paid.

(*b*) It is not a fact that all payments in these villages have been stopped. Payment against certain cane receipts have however been withheld because it has been alleged by the factory that certain bogus receipts were prepared by the persons in charge of the weighment centres. Enquiries in such doubtful cases are being conducted and payments in these cases will be made if these vouchers are proved to be genuine. It has also been reported that no cane was drawn from the village Khirkian and as such all the vouchers made in the name of the said village have been stopped.

(*c*) It is not a fact that all the canegrowers are being harassed and that they have given up cane cultivation to a great extent. Reports indicate that cane cultivation has increased in the area.

(*d*) Steps will be taken to see that the canegrowers who have not got the price of the cane supplied by them get the price as soon as possible.

(*e*) It will be neither in the interest of the country nor of the canegrowers not to allot sugarcane growing areas to Pachrukhi factory. The question of not allotting any cane growing area to Pachrukhi factory does not, therefore, arise. As I have already stated, steps will be taken to see that the canegrowers who have not got the cane price yet get the price of cane.

श्री दारोगा प्रसाद राय—प्रश्न नं० (ए) के जवाब में यह बतलाया गया कि केवल ६७ हजार रुपया शीतलपुर, नयागांव और सोनपुर इलाके का बाकी है लेकिन मैंने यह पूछा था कि सोनपुर स्टेशन के किसानों को कोई रुपया पेमेन्ट हुआ है या नहीं?

श्री महेश प्रसाद सिंह—सोनपुर स्टेशन का कोई फीगर अलग तो मेरे पास नहीं है लेकिन पहले १,८०,७५२ रुपया १४ आना ६ पाई बाकी था जिसमें से अब ६७,६६० रुपया ५ आ० ६ पा० बाकी है।

Shri DAROGA PRASAD ROY : Do Government consider the desirability of making enquiry whether any payment has been paid to the cultivators at Sitalpur station?

Shri MAHESH PRASAD SINHA : Government will look into the matter.

श्री दारोगा प्रसाद राय—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सब किसानों का पेमेन्ट रोका गया है या कहीं-कहीं के किसानों का रोका गया है?

श्री महेश प्रसाद सिंह—कहां-कहां के किसानों का पेमेन्ट रोका गया है इसकी ठीक सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन यह कह सकता हूं कि मुसल्लम पेमेन्ट नहीं रोका गया है। बोगस पुर्जा पकड़ा गया है और उसकी जांच हो रही है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—सोसाइटी का पेमेन्ट रोका गया है या किसी व्यक्ति का पेमेन्ट रोका गया है?

श्री महेश प्रसाद सिंह—दोनों का पेमेन्ट रोका गया है क्योंकि सोसाइटी के हेड-क्लर्क बोगस पुर्जी बनाने में इन्वौल्व्ड हैं।

अध्यक्ष—कौन सोसाइटी के हेडक्लर्क?

श्री महेश प्रसाद सिंह—को-ऑपरेटिव सोसाइटी के हेडक्लर्क।

श्री दारोगा प्रसाद राय—तो क्या सरकार इस बात की जांच कराने जा रही है कि नहीं कि किसानों को जो रुपये नहीं मिले, इसके रेसपौन्सेबुल कौन कर्मचारी हैं?

श्री महेश प्रसाद सिंह—सरकार बहुत जल्द एक आर्डर जारी करने जा रही है कि उन किसानों को जल्द से जल्द पेमेन्ट हो जाय।

श्री दारोगा प्रसाद राय—सरकार ने जवाब में बतलाया कि सोनपुर स्टेशन के किसानों के लिए १ लाख ८० हजार पेबुल था उसमें भी बिल्कुल ६७ हजार ही पेमेन्ट हुआ। तो मेरा पूछना है कि इतना कम क्यों पेमेन्ट हुआ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—हमने कहा है कि ६७ हजार बाकी है और सब पेमेन्ट हो गया है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—तो सरकार उसको एक्सपेडाइट करने के लिए क्या करने जा रही है?

श्री महेश प्रसाद सिंह—हमारे आफिसर इस काम को करने में मुस्तैद हैं कि जल्द पेमेन्ट हो जाय।

श्री दारोगा प्रसाद राय—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नहीं कि यह सिर्फ सोनपुर स्टेशन या किसी दूसरे स्टेशनों के लिए नहीं, बल्कि कुछ गांवों के लिए भी यह पेमेन्ट रुका हुआ है?

श्री महेश प्रसाद सिंह —इस बात की इनक्वायरी हो रही है कि कहां-कहां वोगस काम हुआ है। अगर इनक्वायरी समाप्त हो जायेगी तो जल्द ही पेमेन्ट हो जायेगा।

श्री रामानन्द यादव—क्या सरकार को मालूम है कि यह वोगस पुरजियां किन-किन लोगों की कौंसपिरेसी से बनायी गयी?

श्री महेश प्रसाद सिंह—परचेजिंग एजेन्ट और हेड क्लर्क की कौंसपिरेसी से ऐसी पुरजी बनाई गयीं।

श्री रामानन्द यादव—किस स्टेशन के परचेजिंग एजेन्ट ने ऐसा काम किया?

श्री महेश प्रसाद सिंह—इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यह पार्टिकुलर सवाल है।

श्री रामानन्द यादव—क्या सरकार को यह मालूम है कि नहीं कि ये फैक्टरी के नौमिनेटेड एजेन्ट हैं जो इस तरह का काम आये दिन बराबर किया करते हैं।

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि वोगस पुरजी बनाने का रिमार्क्स सरकार कोआॅपरेटिव सोसाइटी पर लादना चाहती है या किसी दूसरे पर?

श्री महेश प्रसाद सिंह—अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि यह रिमार्क्स हेड क्लर्क पर अभी है, लेकिन यह पता नहीं है कि इसमें कौन-कौन लोग इनवौल्वड हैं।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटी एक स्टेशन को कितनी तादाद में ऊख सप्लाई करती है?

श्री महेश प्रसाद सिंह—तादाद के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—सरकार ने तीन स्टेशन को जो पेमेन्ट दिया है वह क्या बहुत ज्यादा नहीं है?

श्री महेश प्रसाद सिंह—इसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते हैं।

श्री नन्द किशोर नारायण—क्या सरकार को मालूम है कि जो ऊख खरीद होती है और उसका पेमेन्ट होता है वह मिल के द्वारा होता है या यूनियन के द्वारा होता है?

श्री महेश प्रसाद सिंह—जहां तक मुझे खबर है युनियन के द्वारा सप्लाई होता है।

श्री नन्द किशोर नारायण—मैं जानना चाहता हूं कि स्टेशन पर खरीद करने वाले परचेजिंग एजेन्ट हैं या कौन हैं? और बोगस पुरजी बनाने वाले पर सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है?

श्री महेश प्रसाद सिंह—खरीदने वाले कौन हैं, बेचने वाले कौन हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन किसानों का रुपया लोग जरूर खा गए हैं। असल इलजाम तो बोगस पुरजी के बारे में है। इस तरह के बोगस पुरजी पाये गए हैं और इनक्वायरी करने पर पता चला है कि परचेजिंग एजेन्ट और साथ ही साथ हेड क्लर्क दोनों मिल कर बोगस पुरजी बनाये हैं और जब तक जांच नहीं होती है तब तक कोई कार्रवाई कैसे हो सकती है?

HOUSES FOR GOVERNMENT SERVANTS.

356. Shri DAROGA PRASAD ROY : Will the Minister Development (Co-operative) Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that one Pataliputra Co-operative Society, Ltd., has been registered at Patna to construct some houses for Government servants;

(*b*) if the answer to the aforesaid clause be in the affirmative, the progress made in this connection ;

(*c*) by what time the houses are expected to be completed ?